भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन

3451. श्रीमती भारती पारधी:
श्री शशांक मणि:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग के प्रमुख मुद्दों में से कार्बन उत्सर्जन एक है;
(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना राष्ट्रीय इस्पात नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने देश में इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय-सीमा के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में कार्बनीकरण को रोकने और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो की गई विशिष्ट पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) इस क्षेत्र में कार्बनीकरण को रोकने और संसाधन दक्षता बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): जी हां। कार्बन उत्सर्जन एक वैश्विक मुद्दा है और भारतीय इस्पात उद्योग भी इस मुद्दे के प्रति सजग है। इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना राष्ट्रीय इस्पात नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

(ग) से (छ): इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं: -

(1) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों (टास्क फोर्स) की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनींग द स्टील सेक्टर इन इड़िया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस्पात क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, इस्पात क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है और इसके लिए रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करती है।

जारी...2

(2) मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के हरित ट्रांजिशन को सुगम बनाने के लिए कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु हरित इस्पात के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

(3) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना प्रतिपादित की है। इस्पात मंत्रालय इस मिशन में एक हितधारक है और इस मिशन के तहत कोयला/कोक की खपत को कम करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डीआरआई का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना सौंपी गयी है।

(4) इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात विनिर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने की परिकल्पना करती है।

(5) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम सितंबर, 2021, इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना करता है।

(6) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।

(7) राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना इस्पात उद्योग को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

माननीय प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित कोप26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत 2070 तक निवल शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस्पात मंत्रालय इस कथन के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।

****